

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 जून 2017—ज्येष्ठ 13, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जून 2017

क्र. एफ-44-23-15-बीस-2.—यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्र. 147/2014 में एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चों को अलाभित समूह के रूप में सम्मिलित करने का निर्देशन दिया है;

अतः, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 44-84-2010-बीस-2, दिनांक 16 नवम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, मद ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“च. एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चे.”

No. F-44-23-15-XX-2.—WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court has directed in the Write Petition (c) No. 147/2014 to include the children living with or effected by HIV as disadvantaged category;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by of Section 2 (d) of the Right of Children to free and compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F 44-84-2010-XX-2, dated 16th November 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 29th July 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, after item e. and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto shall be added, namely:—

“f. Children living with or effected by HIV.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव.